

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-87
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियाँ

†87. डॉ. अमर सिंह:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के सरकारी स्कूलों में स्वीकृत और रिक्त शिक्षण पदों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्तर-वार (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक) कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और आकांक्षी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण के परिणामों पर शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करने और समयबद्ध तरीके से रिक्त शिक्षण पदों को भरने में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लगातार बनी हुई कमी को दूर करने के लिए कोई राष्ट्रीय रूपरेखा या प्रोत्साहन तंत्र शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। ग्रामीण, जनजातीय और आकांक्षी जिलों सहित सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन, शिक्षक तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और नामांकन में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण समय-समय पर शिक्षकों की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्तर-वार ब्यौरों सहित संस्वीकृत संख्या, पदों पर कार्यरत शिक्षकों, रिक्त शिक्षण पदों और शिक्षकों की भर्ती से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, देश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार की तंत्रों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है। प्रतिस्पर्धी चयन, निरंतरता और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान पर जोर देने के साथ बैठकों और सलाहों के माध्यम से भर्ती की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम पीटीआर बनाए रखने पर जोर दिया गया है। यूडीआईएसई+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 23 है जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के भीतर है।

ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता और व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ करने के

लिए कई पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की गुणवत्ता एवं व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इनमें चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) की शुरुआत, विभिन्न चरणों एवं स्तरों पर शिक्षकों की अपेक्षित दक्षताओं को परिभाषित करने हेतु शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) के दिशा-निर्देशों का विकास, तथा विद्यालयी शिक्षकों को मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) के दिशा-निर्देशों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा) के माध्यम से सेवारत शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल शिक्षण संसाधन एवं ई-सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और शिक्षण क्षमता में निरंतर वृद्धि हो सके।

"सरकारी स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों डॉ. अमर सिंह और श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकारी स्कूलों में शिक्षक (2025-26)

राज्य	सरकारी स्कूलों में कुल शिक्षक 2025-26			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	877	799	893	2189
आंध्र प्रदेश	74616	7254	87545	31710
अरुणाचल प्रदेश	3001	6576	3123	3588
असम	95731	40479	40954	39552
बिहार	164481	242606	635	128339
चंडीगढ़	43	284	2270	2921
छत्तीसगढ़	74645	53452	10282	47760
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	546	1656	271	791
दिल्ली	18287	319	2343	62435
गोवा	1997	321	999	488
गुजरात	27386	153108	3747	10438
हरियाणा	32256	10378	7120	51215
हिमाचल प्रदेश	19080	5243	7270	34674
जम्मू और कश्मीर	18748	38988	17578	16255
झारखंड	35945	45188	16322	18917
कर्नाटक	34830	95197	43325	20292
केरल	16294	15626	6447	44234
लद्दाख	734	2426	1054	1075
लक्षद्वीप	179	192		358
मध्य प्रदेश	128006	122807	43375	105782
महाराष्ट्र	91352	108297	15092	8946
मणिपुर	6615	2944	3896	3515
मेघालय	9964	7587	1054	1692
मिजोरम	5378	5560	2148	1153
नागालैंड	5791	5968	4231	2205
ओडिशा	60916	78991	58487	14771
पुदुचेरी	1513	551	1064	1831
पंजाब	51471	8217	17558	45567
राजस्थान	63341	116481	966	260282
सिक्किम	2038	2220	2485	4190
तमिलनाडु	56778	47102	29931	87640
तेलंगाना	43867	14336	60283	37692

त्रिपुरा	4862	5840	5926	10253
उत्तर प्रदेश	340103	259477	7025	20519
उत्तराखण्ड	22738	7270	5810	23583
पश्चिम बंगाल	239882	18261	27315	162655
भारत	1754291	1532001	538824	1309507

(स्रोत: यूडाइज़+ 2025-26)
